



112

समस्त राजस्व मंडल ग्वालिबर ६ मध्य प्रदेश ६

निगरानी प्र० क्र० R-881-IV/2003

आवेदक :-

1. वितरंजन सिंह आत्मज भगवानदास लोधी
निवासी ग्राम तेवर, तहसील एवं जिला जबलपुर.
2. शरोज पीत श्री राज कुमार भनोट ब
निवासी - गोरखपुर. तहसील व जिला जबलपुर.
3. परसराम आत्मज श्री लाल सिंह लोधी.
निवासी - छोटा पहाड, तहसील व जिला जबलपुर.
4. भारत लाल आत्मज मूल चंद्र साहू
निवासी - ग्राम पिपारवा, तहसील व जिला जबलपुर.
5. हलकाई आत्मज शिवदीन गोठिया.
निवासी - ग्राम पिपारवा, तहसील व जिला जबलपुर.

दिनांक 10-6-03

का जबलपुर मध्य

या श्री प्रेम शिव कारी

कानून दावा प्रस्तुत।

केस
10-6-03
मिडल

विलेख

नामाल

अनावेदक:- 50 प्र० शासन द्वारा तहसीलदार, नजूल
जबलपुर.

अनावेदन पत्र द्वारा - 50 तहसीलदार द्वारा 8 म० प्र० म० राजस्व तीव्रता
1957 के अंतर्गत।

आवेदक निम्न कथन करप्रार्थना करता है कि -

1. यह कि, न्यायालय सक्षम अधिकार अवन लेण्ड तालिम.
जबलपुर के रिकॉर्ड प्र० क्र० - 143 अ / 90, ब - 9, 82 - 83, में
अतिशोष घोषित भूमि का कब्जा लेने सक्षम अधिकारिने तहसीलदार नजूल
को पत्र प्रेषित किया। जिसके आधार पर तहसीलदार नजूल ने
राजस्व प्रकरण क्र० 034अ / 74, 99 - 2000, दर्ज कर. कार्यवाही


R. M.

YXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध 881-तीन/03

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13-6-03 को आदेश पारित किया गया था। बाद में यह तथ्य आने पर कि यह प्रकरण नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 का है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है, अध्यक्ष राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 3-4-12 के द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरावलोकन में लिया गया तथा आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 16-11-12 को आवेदकगण के अधिवक्ता उपस्थित हुये, इसके उपरांत वे लगातार अनुपस्थित हैं। आवेदकों को उपस्थित होने हेतु कई बार सूचना पत्र भेजे गये हैं किंतु वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण में अपना पक्ष रखने में कोई रुचि नहीं है। दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित क्षेत्राधिकार रहित आदेश दिनांक 13-6-2003 निरस्त किया जाता है।</p> <p>2/ उभयपक्ष सूचित हों तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो।</p>	<p> सदस्य</p>